

THE HIGH COURT OF KERALA

Ernakulam - 682031

Email: dsec.hc-ker@gov.in

Fax: 0484 2562451 Phone: 0484 2562963

Dated: 28.04.2025

DII-3 -78782/2023

OFFICIAL MEMORANDUM

Sub: Operationalisation of Maritime Anti-Piracy Act,2022-Designation of

Sessions Court-reg.

Ref: Gazette Notification No. S.O. 1508(E) dated 28.03.2025 of the

Ministry of Home Affairs

A copy of the Notification referred to above is forwarded herewith to all the Principal District Judges and Sections of the High Court for information and necessary action.

(By Order)

Lily G.S

Assistant Registrar(HR.GR)

To

All the Principal District Judges

Copy to

The B, C, D-I, E, Library, I, Filing (C&A), Filing Section, E-Court Cell & ILR Section, High Court
The Administrative Records Section, High Court
The File/Stock File

HRA # 15148 The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28032025-262068 CG-DL-E-28032025-262068

वसाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 14911

No. 14911

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 28, 2025/चैत्र 7, 1947

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 28, 2025/CHAITRA 7, 1947

गृह मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 2025

का.बा.1509(ब).—केंद्रीय सरकार, समुद्री जल दस्युता रोधी अधिनियम, 2022 (2023 का 3) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त और इस संबंध में सक्षम करने वाली अन्य सभी शक्तियों का उपयोग करते हुए -

- (क) भारतीय नौसेना के चीफ पैटी ऑफिसर और उससे ऊपर के रैंक; और भारतीय तट रक्षक के अधिकारी और उससे ऊपर के रैंक को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) के अधीन पुलिस अधिकारी द्वारा यथा प्रयोक्तव्य गिरफ्तारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए; और
- (ख) निम्नलिखित राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के उप-निरीक्षक और उससे ऊपर के रैंक को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) के अधीन पुलिस अधिकारी द्वारा प्रयोक्तव्य किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी, अनुसंधान और अभियोजन की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए, प्राधिकृत करती है;

क्रम संख्या	राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन		उप-निरीक्षक और उससे ऊपर के रैंक के पुलिस अधिकारी
	. *		
1.	गुजरात		नवीबंदर तटीय पुलिस थाना, जिला पोरबंदर।
2.	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	-	वनकबारा तटीय पुलिस स्टेशन और तटीय पुलिस स्टेशन, नानी-दमन।
3.	महाराष्ट्र	-	येलो गेट पुलिस थाना, मुंबई।
4.	गोवा		हार्बर तटीय सुरक्षा पुलिस थाना, मोरमुगाओ हार्बर, जिला दक्षिण गोवा।
5.	कर्नाटक	-	मंगलौर तटीय सुरक्षा पुलिस थाना, जिला दक्षिण कन्नड़, कर्नाटक।
6.	केरल और	e -	फोर्ट कोची तटीय पुलिस थाना, कोची।
	लक्षद्वीप		P 2
7.	तमिलनाडु और	-	बी 5 हार्बर पुलिस थाना, चेन्नई और तटीय सुरक्षा पुलिस
	पुडुचेरी		थाना, तूतुकुडी ।
8.	आंध्र प्रदेश		तटीय पुलिस थाना, विशाखापट्टनम ।
9.	ओडिशा	-	पारादीप मरीन पुलिस थाना, जिला जगतसिंहपुर ।
10.	पश्चिम बंगाल	-	नयाचर तटीय पुलिस थाना, जिला पूर्व मेदिनीपुर ।
11.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	-	केन्द्रीय अपराध स्टेशन, पोर्ट ब्लेयर।

[फा. सं. 1/3/2023- तटीय सुरक्षा]

पौसुमी बसु, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 24th March, 2025

- S.O. 1509(E).—In exercise of the powers conferred by section 6 of the Maritime Anti-Piracy Act, 2022 (3 of 2023), hereinafter referred to as said Act, and all other powers enabling in this behalf, the Central Government hereby authorizes –
- (a) the rank of Chief Petty Officer and above of the Indian Navy; and the rank of Adhikari and above of the Indian Coast Guard to exercise the powers of arrest as exercisable by a police officer under the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023) for the purposes of the said Act; and
- (b) the rank of Sub-Inspector and above, of the following State Governments and Union territory Administrations, to exercise the powers of arrest, investigation and prosecution of any person as exercisable by a police officer under the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023) for the purposes of the said Act:-

Serial number	State Governments or Union territory Administrations		Police officers of rank of Sub-Inspector and above
1.	Gujarat	-	Navibandar Coastal Police Station, District Porbandar.
2.	Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu	-	Vanakbara Coastal Police Station and Coastal Police Station, Nani-Daman.

Central Crimes Station, Port Blair.

11.

Andaman

Islands

Nicobar

and

[No. 1/3/2023-Coastal Security] PAUSUMI BASU, Jt. Secy.



सी.जी.-डी.एल.-अ.-28032025-262070 CG-DL-E-28032025-262070

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1490]

No. 1490]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 28, 2025/चैत्र 7, 1947 NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 28, 2025/CHAITRA 7, 1947

गृह मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 2025

का.बा.1508(ब).—केंद्रीय सरकार, समुद्री जल दस्युता रोधी अधिनियम, 2022 (2023 का 3) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 8 के अधीन प्रदत्त और इस संबंध में सक्षम करने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्रों के सेशन न्यायालयों को अभिहित न्यायालय के रूप में नाम्निदिस करती है, अर्थातु:-

202 (202)(20)			
क्रम संख्या	राज्य या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन का नाम		अभिहित सेशन न्यायालय
1.	गुजरात	-	अतिरिक्त जिला न्यायाधीश का न्यायालय ,पोरबंदर ।
2.	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	-	प्रधान जिला और सेशन न्यायाधीश का न्यायालय, दीव और प्रधान जिला और सेशन न्यायाधीश का न्यायालय, दमन।
3.	महाराष्ट्र	-	शहर सिविल और सेशन न्यायालय, मुंबई की मुख्य शाखा कोर्ट रूम नंबर 28।
4.	गोवा	-	जिला न्यायाधीश-2 और अपर सेशन न्यायाधीश का न्यायालय, मडगांव , दक्षिण गोवा।

(1)

5.	कर्नाटक	-	विशेष न्यायालय के रूप में प्रधान जिला और सेशन न्यायालय दक्षिण कनाड़ा मंगलुरू कर्नाटक।
6.	केरल और लक्षद्वीप	-	अपर विशेष सेशन न्यायालय - (विशेष पुलिस स्थापन या केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरों) ॥, एर्नाकुलम।
7.	तमिलनाडु और पुडुचेरी	-	प्रधान न्यायाधीश, सिटी सिविल न्यायालय, चेन्नई और प्रधान जिला न्यायालय, थूथुकुडी।
8.	आंध्र प्रदेश	-	बारहवां अपर जिला और सेशन न्यायालय, विशाखापत्तनम ।
9.	ओडिशा	1.0	सेशन न्यायाधीश न्यायालय, जगतसिंहपुर।
10.	पश्चिम बंगाल	-	अपर सेशन न्यायाधीश का न्यायालय, हल्दिया, पूर्व मेदिनीपुर।
11.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	-	दक्षिण अंडमान जिले में अपर जिला और सेशन न्यायधीश का न्यायालय न्यायाधीश, पोर्ट ब्लेयर और अपर जिला और सेशन न्यायाधीश, मायाबंदर।

[फा. सं. 1/3/2023- तटीय सुरक्षा] पौसुमी बसु, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 24th March, 2025

S.O. 1508(E).—In exercise of the powers conferred by section 8 of the Maritime Anti-Piracy Act, 2022 (3 of 2023), hereinafter referred to as said Act, and all other powers enabling in this behalf, the Central Government for the purposes of the said Act, hereby designates the Sessions Courts of the following State Governments and Union territory Administrations as mentioned against each as Designated Courts, namely: -

Serial	Name of state		Designated Sessions Court
number	Union territo	ry	
	Administrations	2	
1.	Gujarat	-	Court of Additional District Judge, Porbandar.
2.	Dadra and Nag Haveli and Dam and Diu		The Court of Principal District and Sessions Judge, Diu and the Court of Principal District and Sessions Judge, Daman.
3.	Maharashtra	-	Court Room No.28 at Main Branch at City Civil and Sessions Court, Mumbai.
4.	Goa	-	Court of the District Judge-2 and Additional Sessions Judge, Margao South, Goa.
5.	Karnataka	=	Principal District and Sessions Court, Dakshina Kannada Mangaluru as Special Court, Karnataka.
6.	Kerala a Lakshadweep	nd -	The Additional Special Sessions Court (Special Police Establishment or Central Bureau of Investigation)-III, Ernakulam.
7.	Tamil Nadu aı Puducherry	nd -	Principal Judge, City Civil Court, Chennai and the Principal District Court, Thoothukudi.
8.	Andhra Pradesh	-	Court of XII Additional District and Sessions Court, Visakhapatnam.
9.	Odisha	+	Court of Sessions Judge, Jagatsinghpur.
10.	West Bengal		Court of Additional Sessions Judge, Haldia, Purba Medinipur.
11.	Andaman ar Nicobar Islands	nd -	The court of Additional District and Sessions Judge, Port Blair, South Andaman District; and the Additional District and Sessions Judge, Mayabunder.

[F. No. 1/3/2023-Coastal Security] PAUSUMI BASU, Jt. Secy.